**भारत सरकार**
**संचार मंत्रालय**
**दूरसंचार विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं.1720**
**दिनांक 30 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ**

**पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में बीएसएनएल को पुनर्जीवित करना**

**1720. श्री गुरजीत सिंह औजलाः**
क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बीएसएनएल, जो कभी भारत और पंजाब में दूरसंचार की रीढ़ थी, विशेष रूप से अमृतसर जैसे सीमावर्ती जिलों में, खराब बुनियादी ढांचे, कमजोर रखरखाव, कर्मचारियों की कमी, फाइबर और डिश कनेक्टिविटी की कमी के कारण तेजी से पतन की ओर अग्रसर है, जबकि निजी ऑपरेटर दूरदराज और संवेदनशील क्षेत्रों में पूरी तरह से प्रवेश करने में असमर्थ हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव पंजाब में बीएसएनएल के लिए एक व्यापक पुनरुद्धार योजना तैयार करने का है, जिसमें टावर बुनियादी ढांचे को उन्नत करना, फाइबर कनेक्टिविटी में सुधार करना, स्थानीय रोजगार को बढ़ाना, सीमावर्ती गांवों में विश्वसनीय सेवाएं सुनिश्चित करना शामिल है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और कनेक्टिविटी दोनों महत्वपूर्ण हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बीएसएनएल का व्यापक पहुंच का इतिहास रहा है और यह ऐसा एकमात्र ऑपरेटर है और इसमें ऐसे क्षेत्रों में डिजिटल समावेशन, सुरक्षा संचार और आर्थिक कार्यकलाप को बहाल करने की क्षमता है, व सीमावर्ती क्षेत्रों में बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए एक विशेष पैकेज पर विचार करने का सरकार का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री**
**(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)**

**(क) से (ग)** दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने के लिए बीएसएनएल अखिल भारत स्तर पर संस्थापना हेतु एक लाख स्वदेशी रूप से विकसित 4जी साइट्स रोल आउट कर रहा है। दिनांक 30.06.2025 तक की स्थिति के अनुसार 95,537 साइट्स संस्थापित कर दिए गए हैं और 90,035 4जी साइट्स ऑन-एयर हैं। पंजाब में बीएसएनएल ने सीमावर्ती जिलों में 1,185 4जी बीटीएस और अमृतसर जिले में 359 4जी बीटीएस सहित कुल 3,611 4जी बीटीएस संस्थापित किए हैं। भारत नेट परियोजना के तहत दिनांक 14.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार, पंजाब की कुल 12,668 ग्राम पंचायतों (जीपी) को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी (ओएफसी) से जोड़ा जा चुका है।

इसके अलावा, संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को माँग के आधार पर सभी ग्राम पंचायतों और गाँवों तक फाइबर पहुँचाने के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 04.08.2023 को अनुमोदित किया गया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 करोड़ उच्च गति एफटीटीएच ब्रॉडबैंड कनेक्शनों का प्रावधान भी शामिल है। इस स्कीम के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी बीएसएनएल है।

सीमावर्ती और सुदूर क्षेत्रों में नेटवर्क कवरेज का और आगे विस्तार करने के लिए सरकार 4जी सेचुरेशन स्कीम, बॉर्डर आउट पोस्ट (बीओपी)/ बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट (बीआईपी) आदि जैसी विभिन्न स्कीमें लागू कर रही है। इन स्कीमों का विवरण https://usof.gov.in पर उपलब्ध है।

*****